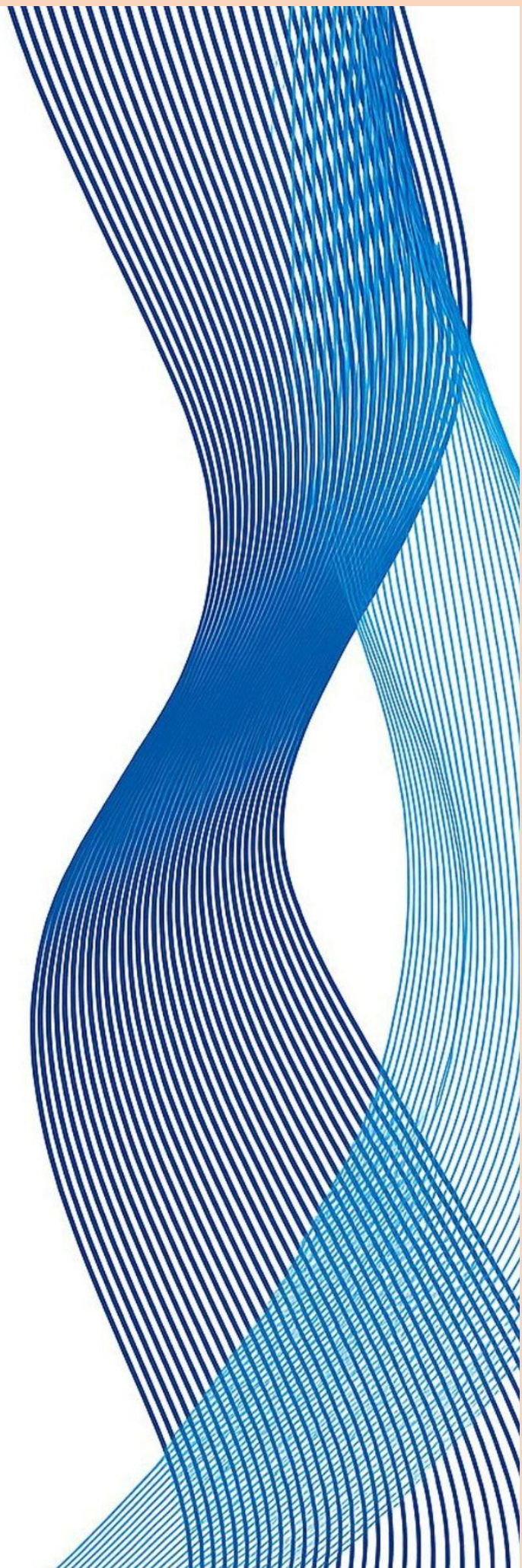




Daily करेंट अफेयर्स

» 29 जून 2025



NATIONAL AFFAIRS / GOVERNMENT SCHEME

1. सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली समुद्री NBFC-सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया



26 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SMFCL) का उद्घाटन किया, जो भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का शुभारंभ था जो पूरी तरह से समुद्री क्षेत्र को समर्पित है।

● यह कार्यक्रम नई दिल्ली में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और MoPSW सचिव टी.के. रामचंद्रन भी शामिल हुए। इस पहल का उद्देश्य विज़न 2047 के अनुरूप समुद्री बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को अनलॉक करना है।

● सर्बानंद सोनोवाल ने इस कार्यक्रम में तीन प्रमुख डिजिटल पहलों का भी अनावरण किया - SAGAR SETU, C-DAC के सहयोग से डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DCoE) और दृष्टि निगरानी मंच - जिन्हें बंदरगाह संचालन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Key Points:-

(i) सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे पहले सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा

औपचारिक रूप से NBFC के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह एक मिनी रत्न, श्रेणी-I CPSE (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) है।

(ii) SMFCL से बंदरगाह और समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय खामियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इसकी संरचना पीएम गति शक्ति और अमृत काल विज़न 2047 जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विशेषीकृत ऋण देने की अनुमति देती है।

(iii) यह कदम सरकार द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के व्यापक प्रयास के अनुरूप है। यह एक स्थायी वित्तीय ढांचे के माध्यम से बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, रसद आधुनिकीकरण और एकीकृत तटीय विकास में निजी निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा।

2. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया।



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाल ही में रणथंभौर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर लंबे वन्यजीव गलियारे का उद्घाटन किया। इसमें पाँच पशु ओवरपास और 1.2 किलोमीटर का अंडरपास शामिल है, जो इसे भारत का सबसे लंबा पर्यावरण-संवेदनशील एक्सप्रेसवे खंड बनाता है।

● रणथंभौर-चंबल बफर जोन में स्थित इस कॉरिडोर में बाघों, भालुओं और अन्य वन्यजीवों के सुरक्षित आवागमन के लिए पांच 500 मीटर लंबे पशु पुल और 1.2 किमी लंबा अंडरपास है।

● एक्सप्रेसवे का लगभग 5 किमी हिस्सा परिदृश्य के साथ मेल खाने के लिए ऊंचा या धंसा हुआ बनाया गया है। ऊंची चारदीवारी और ध्वनि अवरोधक ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं और वन्यजीवों की घुसपैठ को कम करते हैं।

● भारतीय वन्यजीव संस्थान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित यह गलियारा पर्यावास की रूपरेखा के अनुरूप है, तथा वृक्षारोपण प्राकृतिक आवरण सुनिश्चित करता है, जिससे पशु उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

Key Points:-

(i) 35,000 से अधिक देशी पेड़ लगाए गए; प्रत्येक 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन; ड्रिप सिंचाई से पानी का उपयोग 50% से अधिक कम हो गया; कम अपशिष्ट मॉड्यूलर निर्माण को अपनाया गया।

(ii) कैमरा ट्रैप ने पहले ही ओवरपास का उपयोग करते हुए बाघों और भालुओं को देखा है - जो गलियारे की प्रभावशीलता को दर्शाता है और हरित बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर साबित होता है।

3. अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह का नेतृत्व किया।



26 जून, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (MHA) के तहत राजभाषा विभाग (DoL) की 50वीं वर्षगांठ (स्वर्ण जयंती) समारोह की अध्यक्षता की। यह आयोजन प्रशासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

● इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिन्होंने DoL की पांच दशक की यात्रा (1975-2025) के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला।

● सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने "हिंदी शब्दसिंधु" नामक एक गतिशील शब्दावली बैंक की शुरुआत की, जिसे अन्य भाषाओं के सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्दों को एकीकृत करके हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य हिंदी को अधिक समावेशी और प्रशासनिक रूप से प्रासंगिक बनाना है।

● अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि राजभाषा विभाग ने भाषा आधारित शासन के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक स्वाभिमान को बढ़ावा देने और बहुभाषी प्रशासन में संचार अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

Key Points:-

(i) राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि

सरकारी संस्थाओं में आधिकारिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित संवैधानिक और कानूनी आवश्यकताओं का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो।

(ii) भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाने में केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों को सहयोग देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग नामक एक नया प्रभाग भी स्थापित किया गया है, जिससे आधिकारिक संचार में समावेशिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।

(iii) इस समारोह ने न केवल DoL की ऐतिहासिक यात्रा को चिह्नित किया, बल्कि भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शासन में क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

4. केरल संरक्षित क्षेत्रों की राष्ट्रीय 'प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईईई)' रैंकिंग (2020-25 चक्र) में शीर्ष पर है।



केरल ने 2020-25 की समीक्षा अवधि के लिए भारत भर के राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और 'बहुत अच्छा' श्रेणी की रेटिंग हासिल की है।

● केरल ने 76.22% का औसत MEE स्कोर हासिल किया, जिससे उसे 'बहुत अच्छा' ग्रेड मिला - जो केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में चंडीगढ़ (85.16%) के बाद दूसरे स्थान पर है।

● केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क ने 92.97% का प्रभावशाली रिकॉर्ड दर्ज किया, जो दाचीगाम नेशनल पार्क (J&K) के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, मथिकेट्टन शोला एनपी (90.63%) और चित्रार वन्यजीव अभयारण्य भी शीर्ष छह संरक्षित क्षेत्रों में स्थान पर हैं।

● केरल के 21 संरक्षित क्षेत्रों में से 20 में सुधार दिखा, जो मूल्यांकन अवधि में प्रभावी प्रबंधन को दर्शाता है। कोच्चि में केवल मंगलवनम पक्षी अभयारण्य में गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण शहरी प्रदूषण और प्रबंधन योजना का अभाव था।

Key Points:-

(i) कुछ अभयारण्यों को मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकीय तनाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य जंगली मवेशियों के दबाव से ग्रस्त है, जबकि वायनाड वन्यजीव अभयारण्य मानव-हाथी संघर्ष और अतिक्रमण का सामना करता है। रिपोर्ट में आदिवासी बस्तियों के पुनर्वास, आक्रामक प्रजातियों पर नियंत्रण, वन्यजीव गलियारे को जोड़ने और पारिस्थितिकी-विकास समितियों को मजबूत करने की सिफारिश की गई है।

(ii) मंत्रालय के 2020-25 MEE चक्र ने 438 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का मूल्यांकन किया, जिससे औसत स्कोर में 64.41% (2015-20 में 60.52% से) सुधार हुआ। कुल 84 संरक्षित क्षेत्रों को 'बहुत अच्छा' रेटिंग मिली - राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में केरल और चंडीगढ़ शीर्ष पर रहे।

(iii) केरल का मजबूत स्कोर जैव विविधता से समृद्ध पश्चिमी घाट में जैव विविधता संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IUCN-WCPA मानकों पर आधारित MEE ढांचा, आवास संपर्क में सुधार, वन्यजीव संघर्ष को कम करने और समुदायों को टिकाऊ प्रबंधन में शामिल करने के लिए भविष्य-केंद्रित कार्यों का समर्थन करता है।

5. बिहार ने पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया।



26 जून 2025 को, बिहार सरकार ने सीतामढ़ी जिले में उनके पौराणिक जन्मस्थान पुनौरा धाम में देवी सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर के व्यापक विकास और निर्माण की देखरेख के लिए “श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति” नामक नौ सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया।

- बिहार के मुख्य सचिव को ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि विकास आयुक्त उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, तथा सीतामढ़ी के जिला मजिस्ट्रेट और उप विकास आयुक्त क्रमशः सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ट्रस्ट के शेष पांच सदस्यों में प्रमुख अधिकारी और स्थानीय मठ के महंत (मुख्य पुजारी) शामिल हैं, जो प्रशासनिक और आध्यात्मिक निगरानी का मिश्रण सुनिश्चित करते हैं।

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून, 2025 को अंतिम वास्तुशिल्प डिजाइन साझा किया, जिसमें खुलासा किया गया कि नोएडा स्थित एक फर्म - जो पहले अयोध्या राम मंदिर परियोजना से जुड़ी थी - मास्टर प्लान विकसित करेगी। मंदिर को भव्य पैमाने पर बनाया गया है, जिसकी डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर से प्रेरित है।

- राज्य मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक विकास के लिए लगभग ₹120 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से पुनौरा धाम में लगभग 17 एकड़ भूमि पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। अतिरिक्त 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है,

जिससे मंदिर परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 67 एकड़ हो जाएगा, जिसमें मंदिर, उद्यान, परिक्रमा पथ, पार्किंग, कैफेटेरिया, प्रदर्शनी स्थल और बहुत कुछ शामिल होगा।

Key Points:-

(i) ऑनलाइन सार्वजनिक योगदान की सुविधा के लिए एक 3D मॉडल और पोर्टल प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे दुनिया भर के भक्त दान कर सकें। मंदिर की आधारशिला 13 दिसंबर, 2023 को रखी गई थी और ट्रस्ट का लक्ष्य 24 महीने के भीतर महत्वाकांक्षी निर्माण पूरा करना है। अगस्त 2025 तक उद्घाटन की उम्मीद है।

(ii) पुनौरा धाम में हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं, जिनमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भी शामिल हैं। नए मंदिर परिसर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने, मिथिला को अयोध्या से सांस्कृतिक रूप से जोड़ने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।

(iii) यह विश्वास-आधारित दृष्टिकोण डिज़ाइन, वित्तपोषण और क्रियान्वयन की समन्वित निगरानी सुनिश्चित करता है। उच्च स्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व, विशेषज्ञ वास्तुशिल्प योजना और मजबूत जनसहभागिता रणनीतियों के साथ, यह परियोजना अयोध्या के राम मंदिर की सफलता को दोहराने का लक्ष्य रखती है—जिससे पुनौरा धाम एक जीवंत आध्यात्मिक गंतव्य में परिवर्तित हो सके।

6. केंद्र ने जनजातीय योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु ‘आदिकर्मयोगी’ कार्यक्रम शुरू किया।



जून 2025 में, भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी के तहत एक लक्षित प्रशिक्षण पहल आदिकर्मयोगी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों को लागू करने वाले अधिकारियों के बीच क्षमता निर्माण करना है ताकि बेहतर क्रियान्वयन और सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

- आदिकर्मयोगी को जनजातीय कल्याण योजनाओं जैसे कि PESA, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और TSP/MABG-वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

- यह कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के तहत विकसित एक विषयगत मॉड्यूल है और iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर होस्ट किया गया है। यह अधिकारियों को जनजातीय प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए भूमिका-विशिष्ट ई-लर्निंग, केस स्टडी और मूल्यांकन उपकरण प्रदान करता है।

- आदिकर्मयोगी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता, सामुदायिक परामर्श, लाभार्थी सत्यापन, प्रभावी संसाधन आवंटन और शिकायत निवारण जैसे विषय शामिल हैं, जो जनजातीय समूहों के लिए सम्मानजनक और समावेशी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

Key Points:-

(i) यह पहल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य स्तरीय जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TSCs) जैसे क्षमता निर्माण एजेंसियों का एक संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यीय संदर्भों के अनुरूप एक मानकीकृत प्रशिक्षण ढांचा तैयार करना है, जो क्षेत्रीय कर्मियों को नीतिनिर्माताओं से जोड़ता है।

(ii) मापन योग्य प्रभाव संकेतकों में जनजातीय शासन में प्रमाणित अधिकारियों की संख्या, क्षेत्र-स्तरीय निगरानी और योजना लेखापरीक्षा स्कोर में सुधार, तथा कार्यान्वयन अंतराल में उल्लेखनीय कमी के माध्यम से लाभार्थी संतुष्टि में वृद्धि शामिल है।

INTERNATIONAL

1. विश्व बैंक और IAEA ने विकासशील देशों में सुरक्षित परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।



विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने 26 जून, 2025 को पेरिस में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य विकासशील देशों को सुरक्षित और टिकाऊ परमाणु ऊर्जा समाधान, विशेष रूप से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) अपनाने में मदद करना है, ताकि सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए उनकी बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा किया जा सके।

● दशकों में यह पहली बार है कि विश्व बैंक ने परमाणु ऊर्जा के लिए समर्थन दिखाया है। ऐतिहासिक रूप से, संस्था ने परमाणु परियोजनाओं के वित्तपोषण से खुद को दूर रखा था, लेकिन स्वच्छ और विश्वसनीय बेसलोड बिजली की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, बैंक ने अपना रुख संशोधित किया है। IAEA के साथ साझेदारी स्वच्छ विकास रणनीतियों में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने की दिशा में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत का संकेत देती है।

● यह सहयोग परमाणु ऊर्जा से जुड़ी विश्व बैंक परियोजनाओं के लिए ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण और तकनीकी मार्गदर्शन का समर्थन करेगा। यह विश्व बैंक को परमाणु सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा, ईंधन चक्र नियोजन और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन में आंतरिक विशेषज्ञता बनाने में भी मदद करेगा - ऐसे क्षेत्र जहां IAEA का वैश्विक नेतृत्व लंबे समय से है।

● इस समझौते का मुख्य ध्यान छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के विकास और सुरक्षित तैनाती पर है, जो छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त कॉम्पैक्ट, लागत प्रभावी परमाणु प्रणाली हैं। ये रिएक्टर सीमित बिजली बुनियादी ढांचे वाले देशों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे प्रमुख पर्यावरणीय जोखिमों के बिना स्केलेबल ऊर्जा प्रदान करते हैं।

Key Points:-

(i) यह पहल व्यापक वैश्विक जलवायु एजेंडे के अनुरूप है और 2050 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लिए COP28 में की गई प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में है।

(ii) कई विकासशील देशों में 2035 तक बिजली की मांग दोगुनी से अधिक होने की उम्मीद के साथ, विश्व बैंक एक "सभी-में-से-एक" रणनीति अपना रहा है जिसमें स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर, पवन, जलविद्युत और अब परमाणु ऊर्जा शामिल है।

(iii) परमाणु वित्तपोषण पर अपने ऐतिहासिक प्रतिबंधों को हटाकर, विश्व बैंक बहुपक्षीय संस्थाओं और निजी निवेशकों को स्वच्छ परमाणु प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए

प्रोत्साहित कर रहा है। इस कदम से नए वित्तपोषण के स्रोत खुलने और वैश्विक दक्षिण में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु और विकास वित्तपोषण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

2. संयुक्त राष्ट्र ने 80वीं वर्षगांठ पर अपनी वैश्विक भूमिका को पुनर्जीवित करने के लिए 'यूएन80 पहल' शुरू की।



संयुक्त राष्ट्र के 80वें वर्ष के अवसर पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में महत्वाकांक्षी UN 80 पहल की शुरुआत की है, जो एक व्यापक सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य वैश्विक शांति, विकास, मानवीय सहायता और सतत वित्तपोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है।

● अंडर-सेक्रेटरी-जनरल गाय राइडर (नीति) के नेतृत्व में यूएन 80 टास्क फोर्स को तीन मुख्य विषयों पर केंद्रित सिस्टम-वाइड सुधारों को आगे बढ़ाने का काम सौंपा गया है: आंतरिक दक्षता में सुधार, सदस्य-राज्य जनादेशों के कार्यान्वयन की जांच करना और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों में व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनों पर विचार करना। यह पहल पैक्ट फॉर द फ्यूचर और यूएन 2.0 जैसे पहले के प्लेटफार्मों पर आधारित है।

● पहला ट्रैक प्रशासनिक अनुकूलन को लक्षित करता है - नौकरशाही को सुव्यवस्थित करना, उच्च लागत वाले ड्यूटी स्टेशनों (जैसे, न्यूयॉर्क, जिनेवा) से संचालन को स्थानांतरित करना, IT सेवाओं को केंद्रीकृत करना, और

स्वचालन और डिजिटल उपकरणों को बढ़ाना। कैथरीन पोलाई (अवर-महासचिव) के नेतृत्व में एक कार्य समूह द्वारा जून के अंत तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की उम्मीद है।

Key Points:-

(i) दूसरी धारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा और अन्य अंगों द्वारा जारी किए गए लगभग 4,000 शासनादेशों की समीक्षा करती है। इनमें से कई पुराने या ओवरलैपिंग हैं - और इस समीक्षा का उद्देश्य, AI और डेटा एनालिटिक्स की सहायता से, आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना है, जबकि सदस्य देशों से शासनादेश जारी रखने पर निर्णय लेने का आग्रह करना है।

(ii) तीसरा स्तंभ संयुक्त राष्ट्र की व्यापक संरचना और कार्यक्रम संरक्षण का आकलन करता है। 50 से अधिक सुधार सुझाव पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, यह धारा शांति और सुरक्षा, मानवाधिकार, विकास और मानवीय कार्रवाई से संबंधित एजेंसियों को फिर से संगठित करने का प्रयास करती है, जिससे सुसंगतता और बजटीय युक्तिकरण सुनिश्चित होता है।

(iii) ये सभी सुधार संयुक्त राष्ट्र में गंभीर नकदी संकट के कारण हैं, जो देरी से या अपर्याप्त सदस्य योगदान के कारण और भी बढ़ गया है। 193 सदस्यों में से केवल 75 ही 2025 का पूरा बकाया (कुल बजट: 3.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर) चुका रहे हैं, इसलिए कटौती में शांति अभियानों जैसे विभागों में 20% तक कर्मचारियों की कटौती शामिल हो सकती है - जो UN80 की तात्कालिकता और उच्च दांव को उजागर करता है।

BANKING & FINANCE

1. फोनपे और HDFC बैंक ने UPI एकीकरण के साथ रुपये क्रेडिट कार्ड पेश किया।



26 जून, 2025 को, फोनपे और HDFC बैंक ने अपना पहला सह-ब्रांडेड रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ सहज एकीकरण प्रदान करता है। दो वेरिएंट- अल्टीमो और UNO में उपलब्ध यह कार्ड UPI की सुविधा का लाभ उठाता है और साथ ही रोज़ाना के लेन-देन में क्रेडिट रिवॉर्ड भी प्रदान करता है।

- HDFC बैंक द्वारा जारी किया गया यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर काम करता है और इसे सीधे UPI से जोड़ा जा सकता है। उपयोगकर्ता 40 मिलियन से अधिक UPI-स्वीकार करने वाले व्यापारियों के माध्यम से QR-कोड-आधारित क्रेडिट भुगतान कर सकते हैं, जो पारंपरिक क्रेडिट कार्ड को भारत की व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली वास्तविक समय भुगतान प्रणाली से जोड़ता है।

- अल्टीमो वेरिएंट उच्च आवृत्ति वाले खर्च करने वालों को लक्षित करता है, जो फोनपे ऐप खर्च (जैसे, रिचार्ज, बिल, यात्रा, पिनकोड प्लेटफ़ॉर्म) पर 10% रिवॉर्ड पॉइंट देता है, चुनिंदा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर 5% और सभी UPI स्कैन और पे लेनदेन पर 1% देता है। यह हर तिमाही में दो घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी प्रदान करता है। हल्के उपयोगकर्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया UNO संस्करण, फोनपे खर्च पर 2% और ई-कॉमर्स और UPI भुगतान पर 1% देता है।

Key Points:-

(i) कार्डधारक रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करते हैं जिन्हें फोनपे ऐप

या स्मार्ट पोर्टल के माध्यम से भुनाया जा सकता है। अल्टीमो संस्करण में ₹999 की जॉइनिंग फीस दी जाती है, जिसे उनके पहले क्रेडिट-ऑन-UPI लेनदेन और उसके बाद के उपयोग के माध्यम से फोनपे गिफ्ट कार्ड के रूप में वापस किया जा सकता है। कैरा में अक्सर ईंधन अधिभार छूट शामिल होती है।

(ii) संभावित उपयोगकर्ता फोनपे ऐप के भीतर डिजिटल रूप से आवेदन कर सकते हैं। HDFC बैंक द्वारा स्वीकृत होने के बाद, कार्ड जारी किया जाता है और UPI लेनदेन के लिए सहजता से लिंक किया जाता है। बैलेंस चेक, बिल भुगतान, स्टेटमेंट देखना और रिवॉर्ड रिडेम्प्शन सहित सभी खाता प्रबंधन, फोनपे इंटरफ़ेस के माध्यम से संचालित किया जाता है।

(iii) यह लॉन्च फिनटेक एकीकरण की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बिठाते हुए, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड स्पेस में फोनपे के प्रवेश को चिह्नित करता है। 610 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं और एक विशाल UPI स्वीकृति नेटवर्क के साथ, फोनपे रोज़मर्रा के वाणिज्य में क्रेडिट जैसी अधिक सुविधा प्रदान करता है। HDFC बैंक डिजिटल-फर्स्ट ग्राहकों तक पहुँचने के लिए अपने मजबूत क्रेडिट इकोसिस्टम का लाभ उठाता है।

2. RBI का ई-रुपया: भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC-R) का उपयोग कैसे करें।



दिसंबर 2022 से, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं और व्यापारियों को सुरक्षित, नकद-समतुल्य लेनदेन की पेशकश करने के लिए एक बंद पायलट के माध्यम से ई-रुपी (डिजिटल रुपया) - एक टोकन-आधारित, संप्रभु मुद्रा का डिजिटल संस्करण - जारी किया है।

● ई-रुपी (e₹) भारत की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) है, जो पूरी तरह से RBI द्वारा समर्थित है, यह भौतिक नकदी की तरह काम करती है लेकिन डिजिटल रूप में है। खुदरा संस्करण (CBDC-R) 1 दिसंबर, 2022 को लॉन्च किया जाएगा, जबकि थोक संस्करण (CBDC-W) 1 नवंबर, 2022 को लॉन्च किया जाएगा।

● पायलट शहरों (जैसे, नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर) में पात्र उपयोगकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट और अन्य जैसे सहभागी बैंकों से ई-रुपी वॉलेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को ई-रुपी टोकन लोड करने के लिए अपने बचत बैंक खाते को लिंक करना होगा और डेबिट कार्ड सत्यापित करना होगा - कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है।

● एक बार ई-रुपी टोकन लोड हो जाने के बाद, उपयोगकर्ता व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) भुगतान कर सकते हैं। भुगतान QR कोड स्कैन करके या प्राप्तकर्ता वॉलेट विवरण दर्ज करके किया जाता है। स्थानान्तरण तत्काल होते हैं, 24x7 काम करते हैं, और नियमित बैंकिंग घंटों के बाहर भी संचालित होते हैं।

Key Points:-

(i) ई-रुपी लगभग नकद गोपनीयता प्रदान करता है: गुमनामी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा छोटे लेन-देन का पता लगाना कम संभव है। मजबूत साइबर सुरक्षा वॉलेट की सुरक्षा करती है, और मोबाइल डिवाइस खो जाने पर धन वापस प्राप्त किया जा सकता है। RBI दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट के बिना उपयोग की अनुमति देने के लिए ऑफ़लाइन लेनदेन क्षमताएँ भी विकसित कर रहा है।

(ii) ई-रुपी टोकन भौतिक मुद्रा मूल्यवर्ग (₹2, ₹5, ₹10,

₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500, ₹2,000, साथ ही 50 पैसे और ₹1 के सिक्के) के समान हैं। यह ब्याज रहित है, यानी ई-रुपी बैंक जमा की तरह ब्याज अर्जित नहीं करता है। RBI ई-रुपी को तत्काल निपटान के साथ विनिमय का एक सुरक्षित और लागत प्रभावी माध्यम मानता है और इस पर कोई GST या पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता है।

(iii) शुरुआत में बैंकों की बढ़ती भागीदारी के साथ चार शहरों में शुरू किए गए ई-रुपी नेटवर्क का लक्ष्य एचडीएफसी, कोटक, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे अन्य शहरों और बैंकों तक विस्तार करना है। खुदरा उपयोग तेजी से बढ़ा है - ₹16 करोड़ (मार्च 2023) से ₹1,000 करोड़ (मार्च 2025) तक - जिसमें छह मिलियन उपयोगकर्ता और हजारों व्यापारी शामिल हैं।

● ICRA ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 26 में खुदरा मुद्रास्फीति मध्यम रहेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 3.5% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 25 में दर्ज 4.6% से काफी कम है और मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 3.7% के पूर्वानुमान से भी कम है। इससे नीति स्थिरता की गुंजाइश बन सकती है।

● एजेंसी ने कहा कि मई 2025 में मानसून के जल्दी आने से बिजली और खनन गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि, ICRA को उम्मीद है कि गर्मियों में फसल का मौसम अच्छा रहेगा, और वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में कृषि सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 4.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। पूरे वर्ष के लिए, सामान्य मानसून पैटर्न को मानते हुए, कृषि क्षेत्र में GVA में 3.5% से 4.0% के बीच वृद्धि होने का अनुमान है।

Key Points:-

(i) रिपोर्ट में वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में मिश्रित आर्थिक प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। ICRA द्वारा निगरानी किए गए 17 प्रमुख गैर-कृषि उच्च आवृत्ति संकेतकों में से केवल नौ ने वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2025) की तुलना में सुधार दिखाया, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में मामूली सुधार का संकेत देता है।

(ii) ICRA ने वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में, वैश्विक ब्याज दर चक्रों के बारे में अनिश्चितता और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता जैसी कई बाहरी व्यापक आर्थिक चुनौतियों को चिह्नित किया। ये भारत के विकास पथ पर भारी पड़ सकते हैं और वित्त वर्ष 26 के लिए समग्र आर्थिक दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकते हैं।

(iii) यह GDP पूर्वानुमान ग्रामीण और शहरी मांग, मौद्रिक नीति बाधाओं और पिछले वर्ष के उच्च आधार प्रभावों से मिले-जुले संकेतों की पृष्ठभूमि में आया है। इसके बावजूद, ICRA स्थिर मुद्रास्फीति और अनुकूल नीति ढांचे द्वारा समर्थित भारत की मध्यम अवधि की रिकवरी के बारे में

ECONOMY & BUSINESS

1. ICRA ने भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो RBI के अनुमान से कम है।



जून 2025 में गुरुग्राम स्थित निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि पूर्वानुमान को 6.2% पर बरकरार रखा। यह अनुमान ICRA के जून मैक्रोइकॉनॉमिक अपडेट में प्रकाशित किया गया था और यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.5% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है।

सतर्क आशावाद बनाए रखता है।

2. भारत ने वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया, जो चार तिमाहियों में पहली बार हुआ।



भारत के बाह्य संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (Q4 FY25) की चौथी तिमाही में 13.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का चालू खाता अधिशेष दर्ज किया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.3% है। यह एक साल से अधिक समय में भारत का पहला तिमाही अधिशेष है, जो मुख्य रूप से मजबूत सेवा निर्यात और रिकॉर्ड प्रेषण द्वारा संचालित है।

● वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारत का मजबूत अधिशेष वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चालू खाता घाटे के विपरीत है और यह एक तेज बाहरी सुधार को दर्शाता है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही (वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही) में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का छोटा अधिशेष दर्ज किया गया था। यह बदलाव वैश्विक अस्थिरता के बावजूद व्यापार सेवाओं के बेहतर प्रदर्शन और व्यापक आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) इस अधिशेष में दो प्रमुख योगदानकर्ता थे सेवाओं के निर्यात में तेज़ी और मजबूत प्रेषण। शुद्ध सेवा आय 53.3

बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गई, जो कि वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में दर्ज 42.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा, प्रेषण बढ़कर 33.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो कि भारतीय प्रवासियों से मज़बूत आवक व्यक्तिगत हस्तांतरण का स्पष्ट संकेत है।

(ii) इस सुधार के बावजूद, भारत का व्यापारिक घाटा 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर उच्च स्तर पर बना रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह 52.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, प्राथमिक आय खाता घाटा साल-दर-साल 14.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम होकर 11.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिससे कुल चालू खाता आंकड़ों में और वृद्धि हुई।

(iii) पूरे वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) के लिए, भारत का चालू खाता घाटा (CAD) 23.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.6% है, जो वित्त वर्ष 24 में 0.7% से सुधार दर्शाता है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि वैश्विक कमोडिटी की कीमतों और आयात में तेज़ी के कारण भारत वित्त वर्ष 26 में मामूली CAD पर वापस आ जाएगा। हालाँकि, भारत का मजबूत सेवा क्षेत्र और पूंजी प्रवाह स्थिर भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. जू जियायी को वैश्विक विस्तार का नेतृत्व करने के लिए AIIB की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया।



24 जून, 2025 को, चीन के पूर्व वित्त उप मंत्री, जूजियाई को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह 16 जनवरी, 2026 को पदभार ग्रहण करेंगी, और पाँच साल के कार्यकाल के लिए बैंक की दूसरी अध्यक्ष और पहली महिला नेता दोनों बन जाएँगी।

● जू के पास अंतरराष्ट्रीय वित्त का 30 से ज़्यादा साल का अनुभव है, उन्होंने वित्त के उप मंत्री जैसे वरिष्ठ पदों पर काम किया है और विश्व बैंक समूह, एशियाई विकास बैंक, नए विकास बैंक और अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) में नेतृत्व के पद संभाले हैं। AIIB की 10वीं वार्षिक बैठक में बैंक के बोर्ड अध्यक्ष द्वारा उनके चुनाव की पुष्टि की गई।

Key Points:-

(i) संस्थापक अध्यक्ष जिनलिकुन के दशक भर के कार्यकाल के दौरान, AIIB के सदस्य देशों की संख्या 57 से बढ़कर 110 हो गई, 38 अर्थव्यवस्थाओं में 322 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया गया, एए रेटिंग प्राप्त की और 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल किया।

(ii) बीजिंग स्थित बहुपक्षीय बैंक की पहली महिला प्रमुख के रूप में, जू को "टाइगर-फाइटिंग लेडी जनरल" का अनौपचारिक शीर्षक दिया गया है, जो चीन के केंद्रीय अनुशासन निरीक्षण आयोग में उनके मजबूत रिकॉर्ड का संदर्भ देता है। उनका नेतृत्व AIIB के शासन को वैश्वीकृत करने के प्रयासों के बीच आता है, जबकि इसका मुख्य ध्यान

बुनियादी ढांचे और जलवायु वित्तपोषण पर बना रहता है।

(iii) जू की अध्यक्षता से AIIB के वैश्विक पदचिह्न का विस्तार होने की उम्मीद है, जिसमें हांगकांग, सिंगापुर और लंदन में नए क्षेत्रीय कार्यालय और विश्व बैंक और जापान जैसे पारंपरिक विकास ऋणदाताओं के साथ बढ़ी हुई साझेदारी शामिल है। वह भू-राजनीतिक संरक्षण को संतुलित करने और बढ़ती वैश्विक वित्तपोषण बहुध्रुवीयता के बीच AIIB की भूमिका को मजबूत करने के लिए तैयार हैं।

2. अमिताभ कांत को भारत के जी-20 शेरपा के पद से हटने के बाद कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया।



जून 2025 में वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह अमिताभ कांत को कनाडा स्थित वैश्विक बीमा और निवेश फर्म फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। हाल ही में उन्होंने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे सार्वजनिक सेवा में उनके 45 साल के करियर का अंत हो गया।

● अमिताभ कांत फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन और उसके सहयोगियों को भारत की "विकसित भारत" पहल के साथ जुड़े रणनीतिक निवेश अवसरों की पहचान करने में मार्गदर्शन करेंगे - जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है।

• फेयरफैक्स पहले से ही बीमा, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और हवाई अड्डे के संचालन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है, जिसमें गो डिजिट जनरल इश्योरेंस और बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी संस्थाओं में हिस्सेदारी है।

Key Points:-

(i) अमिताभ कांत नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में अपने कार्यकाल से बहुत अनुभव लेकर आए हैं, जहाँ उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रमों का नेतृत्व किया और भारत की ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग में 79 स्थानों का सुधार किया। उन्होंने पहले भारत के जी20 शेरपा के रूप में भी काम किया, जो 2023 नई दिल्ली घोषणा के लिए आम सहमति बनाने में सहायक रहे।

(ii) फेयरफैक्स के चेयरमैन और CEO प्रेम वत्सा ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी नवीनीकरण, औद्योगिक सुधार और पर्यटन के क्षेत्र में कांत के गहन ज्ञान की प्रशंसा की। वत्सा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कांत के मूल्य - ईमानदारी, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा - फेयरफैक्स के कॉर्पोरेट सिद्धांतों के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं।

(iii) यह रणनीतिक नियुक्ति फेयरफैक्स की भारत में दीर्घकालिक निवेश रणनीति को रेखांकित करती है। कांत की भूमिका से नीतिगत अंतर्दृष्टि, सार्वजनिक-निजी समन्वय और सतत विकास चैनलों का लाभ उठाने की फर्म की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों के बीच विश्वास मजबूत होगा।

3. प्रगनानंद ने उज्ज शतरंज कप जीता और भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त शतरंज खिलाड़ी बने।



जून 2025 के अंत में, भारतीय ग्रैंडमास्टर रमेशबाबू प्रगनानंद ने ताशकंद में एक रोमांचक फाइनल और टाईब्रेक के बाद उज्जेस कप मास्टर्स जीता। इस जीत ने उनकी लाइव FIDE रेटिंग को 2778.3 तक पहुंचा दिया, जिससे वे विश्व स्तर पर शीर्ष 4 खिलाड़ियों में से एक और भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए।

• प्रगनानंद ने प्रतिद्वंद्वी नोडिरबेक अब्दुसत्तोरुव और जावोखिर सिंडारोव को रोमांचक ब्लिट्ज टाईब्रेक में हराकर खिताब जीता। क्लासिकल टूर्नामेंट खुद 5.5/9 पर तीन-तरफा टाई के साथ समाप्त हुआ, लेकिन प्रग ने स्टील की हिम्मत और असाधारण सामरिक सटीकता का प्रदर्शन करते हुए सडन-डेथ प्लेऑफ में जीत हासिल की।

• अब्दुसत्तोरुव के खिलाफ़ उनका अंतिम दौर का क्लासिकल मुकाबला निर्णायक था - प्रैग ने काले मोहरों के साथ शानदार खेल दिखाया, जिससे उनकी स्थिति नाटकीय जीत में बदल गई और टाईब्रेक के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पहले दौर में GM अर्जुन एरिगैसी को भी हराया, जो लचीलापन और रणनीतिक स्पष्टता दोनों को दर्शाता है।

Key Points:-

(i) लाइव FIDE रेटिंग 2778.3 तक पहुंचने के साथ, प्रगनानंद ने अपने हमवतन ग्रैंडमास्टर डी गुकेश (2776.6) को पीछे छोड़ते हुए विश्व रैंकिंग में चौथा स्थान (World No. 4) हासिल कर लिया—जो विश्वनाथन आनंद के बाद किसी भी भारतीय द्वारा प्राप्त अब तक की सबसे ऊंची वैश्विक और

राष्ट्रीय लाइव रैंकिंग है।

(ii) यह 2025 में उनकी तीसरी प्रमुख क्लासिकल टूर्नामेंट जीत है, इससे पहले उन्होंने विज्क आन ज़ी में टाटा स्टील मास्टर्स और सुपरबेट शतरंज क्लासिक रोमानिया में जीत हासिल की थी। प्रत्येक खिताब को कड़े टाईब्रेक के माध्यम से जीता गया - जो दबाव में उनके अद्वितीय क्लच प्रदर्शन को उजागर करता है।

(iii) भारत के शतरंज समुदाय और नेताओं, जिनमें पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन शामिल हैं, ने प्राग की जीत की सराहना की। आनंद ने इसे "चरित्र का एक प्रभावशाली प्रदर्शन" कहा, भारतीय शतरंज के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कद के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. "नीदरलैंड ने हेग में 2025 NATO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और सदस्यों ने 2035 तक 5% GDP रक्षा खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई"।



1949 में NATO की स्थापना के बाद पहली बार नीदरलैंड ने 24-25 जून, 2025 को हेग में NATO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में NATO महासचिव मार्क रूटे की अध्यक्षता में रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग

पर निर्णायक प्रतिबद्धताओं को अपनाने के लिए सभी 32 सदस्य देशों के नेता एक साथ आए।

● नीदरलैंड ने हेग में वर्ल्ड फोरम में अपना पहला नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जो गठबंधन के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। इस शिखर सम्मेलन में 32 NATO देशों ने भाग लिया, जिसमें 45 राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख, 6,000 आधिकारिक प्रतिनिधि और लगभग 2,000 मीडिया कर्मी शामिल थे। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, नीदरलैंड ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षात्मक अभियान - "ऑपरेशन ऑरेंज शील्ड" लागू किया - जिसमें पुलिस, सेना, F-35 जेट और ड्रोन निगरानी सहित 27,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया, साथ ही आयोजन स्थल के आसपास की सड़कों को सप्ताह भर के लिए बंद कर दिया गया।

● शिखर सम्मेलन के एजेंडे में NATO पब्लिक फोरम, रक्षा उद्योग फोरम और कई द्विपक्षीय बैठकें शामिल थीं। पब्लिक फोरम में सभी NATO देशों के अकादमिक नेताओं, नागरिक समाज और युवा आवाज़ों की मेजबानी की गई, जिसमें पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी पर जोर दिया गया। रक्षा उद्योग फोरम में 100 से ज्यादा वैश्विक रक्षा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और रक्षा रसद में नई तकनीकें पेश कीं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया सहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के नेताओं को विशेष रणनीतिक परामर्श के लिए आमंत्रित किया गया।

● शिखर सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक सर्वसम्मति से सहमति थी - कुछ अपवादों को छोड़कर - 2035 तक प्रत्येक सदस्य के सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक राष्ट्रीय रक्षा व्यय को बढ़ाने पर। इसमें पारंपरिक सैन्य क्षमताओं के लिए 3.5% और उभरते खतरों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5% शामिल है। यह लक्ष्य 2029 में मध्यावधि समीक्षा के अधीन होगा। महासचिव मार्क रूटे ने प्रतिबद्धता को "सामूहिक रक्षा तत्परता में एक पीढ़ीगत छलांग" कहा, जबकि कई नेताओं ने इसे शीत युद्ध के बाद

से NATO का सबसे परिवर्तनकारी राजकोषीय समझौता बताया।

Key Points:-

(i) शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 5% लक्ष्य को आगे बढ़ाने का श्रेय लिया, इसे "निष्पक्षता की एक बड़ी जीत" कहा। उन्होंने यूरोपीय देशों से अमेरिकी निर्मित हथियार खरीदने की पुरजोर वकालत की, जो घरेलू औद्योगिक हितों को दर्शाता है। हालाँकि, इस प्रस्ताव का आंतरिक विरोध हुआ। स्पेन ने आधिकारिक तौर पर आर्थिक बाधाओं का हवाला देते हुए 5% लक्ष्य से बाहर निकलने का विकल्प चुना, हालाँकि यह संबंधित सुधारों के लिए 2035 की समयसीमा को बनाए रखने के लिए सहमत हो गया। इटली, स्लोवाकिया और बेल्जियम ने भी रक्षा प्रतिबद्धताओं के साथ सामाजिक कल्याण खर्च को संतुलित करने के बारे में चिंता व्यक्त की।

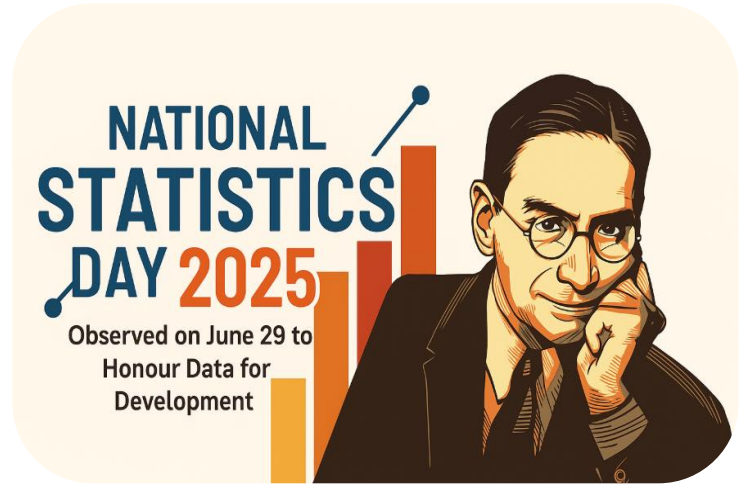
(ii) शिखर सम्मेलन ने अनुच्छेद 5 के तहत NATO के सामूहिक रक्षा सिद्धांत की पुष्टि की और रूस को "दीर्घकालिक, प्रणालीगत खतरे" के रूप में पहचाना। जबकि यूक्रेन वार्ता के केंद्र में नहीं था, राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा मौजूद थे और उच्च स्तरीय वार्ता में शामिल थे। तत्काल सदस्यता पर बहस के बावजूद, NATO ने यूक्रेन की संप्रभुता के लिए समर्थन दोहराया और अद्यतन वायु रक्षा प्रणालियों और युद्धक्षेत्र खुफिया समन्वय सहित निरंतर वित्तीय और सैन्य सहायता का वादा किया।

(iii) शिखर सम्मेलन का समापन "द हेग NATO शिखर सम्मेलन घोषणा 2025" को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ हुआ, जिसमें रक्षा बजट बेंचमार्क, साइबर सुरक्षा सहयोग और रक्षा नवाचार रणनीतियों सहित सभी प्रमुख प्रस्तावों को रेखांकित किया गया। सदस्य देशों ने 2029 में मध्यावधि कार्यान्वयन समीक्षा के लिए फिर से बैठक करने की प्रतिबद्धता जताई। आधिकारिक तौर पर 2026 के नाटो शिखर सम्मेलन के लिए तुर्की को मेज़बान घोषित किया गया। हेग घोषणा को अब 2030 के दशक तक NATO के रणनीतिक मार्ग को आकार देने वाले एक आधारभूत

दस्तावेज़ के रूप में देखा जाता है।

IMPORTANT DAYS

1. विकास के लिए डेटा के सम्मान हेतु 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा।



भारत 29 जून, 2025 को भारतीय सांख्यिकी के अग्रदूत प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 18वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाएगा।

● 2025 के आयोजन की थीम थी "विकास के लिए डेटा का सम्मान", जिसमें साक्ष्य-आधारित नीति, सतत विकास और राष्ट्रीय नियोजन को आगे बढ़ाने में सटीक आंकड़ों की आवश्यक भूमिका पर जोर दिया गया।

● सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा सामाजिक-आर्थिक नियोजन और शासन में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पैनल चर्चाएँ, डेटा प्रसार कार्यशालाएँ और युवा सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं का सम्मान शामिल था।

Key Points:-

(i) 29 जून, 1893 को जन्मे प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने 1931 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना और भारत में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण शुरू करने में एक

आधारभूत भूमिका निभाई। उनके योगदान में महालनोबिस दूरी सूत्र और विकास के लिए सांख्यिकीय दृष्टिकोण के साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना को आकार देना भी शामिल है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में डेटा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख क्षेत्रीय पहल के रूप में मान्यता देता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस अवसर का उपयोग बेहतर सांख्यिकीय प्रशासन के लिए राष्ट्रीय एकीकृत सूचना मंच (NIIP) जैसे अपने डिजिटल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए भी करता है।

(iii) 2025 में, डेटा गुणवत्ता, सांख्यिकीय मॉडलिंग और पारदर्शी रिपोर्टिंग में नवाचार के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य विभागों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने बेहतर नियोजन और विकास परिणामों के लिए भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिक बनाने में एआई और बिग डेटा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर जोर दिया।

2. चुनौतियों और विविधता पर प्रकाश डालने के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 29 जून को मनाया जाएगा।



संयुक्त राष्ट्र (UN) प्रतिवर्ष 29 जून को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करने तथा उनके समक्ष आने वाली पर्यावरणीय और

विकासात्मक चुनौतियों पर प्रकाश डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाता है।

● उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच फैले हुए हैं, जो पृथ्वी के लगभग 40% भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं और वैश्विक जैव विविधता का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं। वे वर्षावनों, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव वनों जैसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों को बनाए रखते हैं, जो जलवायु विनियमन और प्राकृतिक संसाधनों के लिए आवश्यक हैं।

● दुनिया की लगभग 40% आबादी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है, और 2050 तक दुनिया के दो-तिहाई बच्चों के वहां रहने की उम्मीद है। उष्णकटिबंधीय समाजों की विशेषता उल्लेखनीय सांस्कृतिक विविधता, स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ और जीवंत परंपराएँ हैं।

● अपनी समृद्धि के बावजूद, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, वनों की कटाई, शहरी फैलाव और जैव विविधता के नुकसान से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, उच्च गरीबी दर, झुग्गी बस्तियों का प्रसार और पानी की कमी उन्हें वैश्विक झटकों के प्रति अनुपातहीन रूप से संवेदनशील बनाती है।

Key Points:-

(i) पहली 'उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की स्थिति' रिपोर्ट 29 जून 2014 को प्रकाशित हुई थी, और इसकी सफलता के बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2016 में संकल्प A/RES/70/267 को अपनाया, जिसके तहत आधिकारिक तौर पर 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया गया।

(ii) इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक एकजुटता, डेटा-संचालित नीतिगत प्रतिक्रियाओं और सतत उष्णकटिबंधीय विकास के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना है।

(iii) प्रत्येक उत्सव के अवसर पर दुनिया भर की सरकारें, गैर सरकारी संगठन, शोधकर्ता और स्कूल सेमिनार, प्रदर्शनियाँ, पैनल चर्चाएँ और डिजिटल अभियान आयोजित करते हैं। गतिविधियाँ उष्णकटिबंधीय जैव विविधता की रक्षा, लचीली

आजीविका का समर्थन करने और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए नीति निर्माण में समावेशिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।

3. संयुक्त राष्ट्र ने 27 जून 2025 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बधिर-अंधापन दिवस मनाया।

**UN OBSERVED FIRST-EVER
INTERNATIONAL DAY
OF DEAFBLINDNESS
JUNE 27, 2025**



संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 27 जून, 2025 को बधिर-अंधेपन के बारे में वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बधिर-अंधेपन दिवस मनाया - एक अनोखी दोहरी विकलांगता जिसमें दृष्टि और श्रवण दोनों की हानि शामिल है। इस दिवस का उद्देश्य संचार, गतिशीलता, शिक्षा और सूचना तक पहुँचने में बधिर-अंधेपन से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है।

- यह नया अंतर्राष्ट्रीय दिवस बधिर-अंध जागरूकता सप्ताह के अनुरूप है, जो प्रत्येक वर्ष 23 जून से 29 जून तक विश्व स्तर पर मनाया जाता है।

- जागरूकता सप्ताह का 2025 का विषय "नेतृत्व का विकास: साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं" है, जो नेतृत्व की भूमिकाओं और निर्णय लेने वाले स्थानों में बधिर-अंधे समुदाय के सशक्तिकरण और समावेश के महत्व पर जोर देता है।

Key Points:-

(i) इस दिवस को आधिकारिक मान्यता संयुक्त राष्ट्र महासभा

(UNGA) द्वारा 16 जून, 2025 को प्रस्ताव A/RES/79/294 को अपनाने के बाद मिली, जिसके तहत 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय बधिर-अंधता दिवस के रूप में स्थापित किया गया।

(ii) यह तिथि हेलेन केलर की 145वीं जयंती के सम्मान में चुनी गई, जो बधिर-अंधों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वकील और लचीलेपन और वकालत की प्रतीक थीं।

(iii) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 में मनाया जाने वाला यह दिवस 1984 में शुरू किए गए प्रयासों से प्रेरित है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने बधिर-अंधे जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की थी। 1989 में बधिर-अंधे अधिकारों पर स्वीडिश घोषणा के साथ इसे वैश्विक गति मिली, जो विकलांगता समावेशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

DEFENCE

1. ICG ने GSL में 08-FPV परियोजना के तहत पहला तीव्र गश्ती पोत 'आदम्या' शामिल किया।



26 जून, 2025 को भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला फास्ट पैट्रोल वेसल (FPV) "आदम्या" को शामिल किया, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) ने 08-FPV परियोजना के तहत डिजाइन और निर्मित किया है। यह पोत स्वदेशी समुद्री सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में एक छलांग है।

● भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है क्योंकि अदम्या में 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जो उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करती है - जिसमें कंट्रोलबल पिच प्रोपेलर (CPP) और घरेलू गियरबॉक्स शामिल हैं - जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

● 52 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा यह जहाज, जिसकी अधिकतम गति 27 नॉट से अधिक है, अमेरिकी शिपिंग ब्यूरो और भारतीय शिपिंग रजिस्टर से दोहरे प्रमाणन को पूरा करता है। अदम्य ICG बेड़े में पहला FPV है जिसमें CPP-आधारित प्रणोदन की सुविधा है, जो गतिशीलता और परिचालन लचीलेपन में सुधार करता है।

● अत्याधुनिक नौसैनिक प्रणालियों से लैस, FPV में 30 मिमी CRN-91 गन, दो 12.7 मिमी स्थिर रिमोट-कंट्रोल गन, एक एकीकृत ब्रिज सिस्टम (IBS), एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS) और एक स्वचालित पावर प्रबंधन प्रणाली (APMS) है। ये सिस्टम निगरानी, बचाव और प्रवर्तन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं।

Key Points:-

(i) अदम्य को शामिल करने से ICG के मिशन क्षेत्रों - समुद्री कानून प्रवर्तन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) संरक्षण, तटीय निगरानी और खोज एवं बचाव (SAR) कार्यों को बढ़ावा मिलेगा - जो भारत की तटीय सुरक्षा संरचना में एक बल-गुणक के रूप में कार्य करेगा।

(ii) 08-FPVs परियोजना के तहत वितरित किए जाने वाले आठ FPV में से पहले के रूप में, अदम्य भविष्य के जहाजों- 'अक्षर', 'अमूल्य', 'अक्षय', 'अचल' के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जो अगले 24-30 महीनों में सेवा में प्रवेश करेंगे, जिससे भारत के समुद्री रक्षा बुनियादी ढांचे का और विस्तार होगा।

OBITUARY

1. 'कांटा लगा' स्टार शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया।



प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला, जिन्हें "कांटा लगा गर्ल" के नाम से जाना जाता है, का 27 जून, 2025 को मुंबई के अंधेरी स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 42 वर्ष की थीं, शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि उन्हें अचानक हृदयाघात हुआ था - किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं है।

● उस शाम, शेफाली को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसे उसके पति, अभिनेता पराग त्यागी और अन्य लोगों द्वारा बेलव्यू मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। दुखद रूप से, उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को सूचित किया गया, और उसके शव को अनिवार्य पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया।

● प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि उसने अपनी नियमित दवा ली थी और उसे एंटी-एजिंग इंजेक्शन दिया गया था, संभवतः खाली पेट, जिससे उसका रक्तचाप बहुत कम हो गया और हृदय गति रुक गई। घटना में ड्रग्स का संदेह नहीं है।

Key Points:-

(i) शेफाली ने 2002 में वायरल म्यूजिक वीडियो "कांटा लगा" से प्रसिद्धि हासिल की, बाद में मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में अभिनय किया, और नच बलिए सीजन 5 और 7 और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अभिनय किया। उनके हालिया काम में अलौकिक श्रृंखला शैतानी रस्में शामिल हैं।

(ii) मीका सिंह, एली गोनी, दिव्यंका त्रिपाठी, वाहबिज दोराबजी और अन्य हस्तियों ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया और शेफाली को जीवंत और जीवन से भरपूर बताया। विभिन्न पीढ़ियों के प्रशंसकों ने करिश्माई कलाकार के निधन पर शोक व्यक्त किया।

(iii) मुंबई पुलिस ने एक नियमित दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट जारी की है और आधिकारिक तौर पर मौत का कारण घोषित करने से पहले पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी के नतीजों का इंतजार कर रही है। किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं जताई गई है।

Static GK

MoPSW	केंद्रीय मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल	मुख्यालय: नई दिल्ली
International Atomic Energy Agency	महाप्रबंधक : राफेल मारियानो ग्रॉसी	मुख्यालय : वियना, ऑस्ट्रिया
National Highways Authority of India (NHAI)	अध्यक्ष: संतोष कुमार यादव (IAS)	मुख्यालय: नई दिल्ली
Kerala	मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन	राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Netherlands	राजधानी: एम्स्टर्डम	आधिकारिक भाषा: डच
HDFC Bank	CEO : शशिधर जगदीशन	मुख्यालय: मुंबई
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
ICRA Limited	MD और CEO : रामनाथ कृष्णन	स्थापना: 1991
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	स्थापना : 2016	मुख्यालय : बीजिंग, चीन
Indian Coast Guard	महानिदेशक:	मुख्यालय: नई

(ICG)	परमेश शिवमणि	दिल्ली
-------	--------------	--------